(b) if so, what steps have been taken by Government to test the efficacy thereof and with what results; and

(c) what steps are being taken to undertake production and marketing thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को एक अत्याधुनिक एकक बनाए जाने के लिए सहायता

*80. **श्री राम जेठमलानी:**
श्री राम नरेश यादव:

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा, दिल्ली में बिजली सप्लाई की वितरण व अनुरक्षण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए संस्थान को अत्याधुनिक बनाए जाने की अपनी योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के लिए हाल ही में विश्व बैंक के अधिकारियों के साथ बातचीत की गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में वित्तीय प्रशासन में कुप्रबंध के कारण विश्व बैंक के अधिकारियों ने फिलहाल वित्तीय सहायता देने में अपनी असहमति व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा संस्थान में व्याप्त कुप्रबंध को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली के चारों ओर 400 के० वी० पारेषण रिंग स्थापना से संबंधित योजना के क्रियान्वयन का वित्तपोषण करने के लिए डेसू द्वारा वर्ष 1987 में विश्व बैंक के साथ 60 मिलियन डालर के मूल्य के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये गये थे। यह समझौता इस शर्त पर है कि डेसू कुछ निश्चित प्रसंविदाएं पूरा करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसके द्वारा 31 दिसम्बर, 1988 तक एक वसूली योजना बनाया जाना एवं उसका कार्यान्वयन किया जाना शामिल है। डेसू की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए अब एक कार्रवाई योजना तैयार की गई है। बैंक द्वारा ऋण का संवितरण अस्थाई रूप से स्थगित कर दिया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Discontentment among the Employees of Public Sector

482. SHRI MOHAMMED AMIN: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the serious discontentment among the public sector employees in the country;

(b) if so, what are there grievances at present;

(c) what steps Government have taken or propose to take to redress their grievances;

(d) whether Government will take immediate steps so that a confrontation is avoided in the immediate future; and

(e) if so, what are the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) to (e) The main reason for the discontentment among the public sector employees is the delay in finalisation of long-term wage settlements. Government have already laid down a wage policy and the Managements of public sector enterprises and the workers have to finalise wage settlements within the parameters of the wage policy bilaterally. However Govt, have also emphasised the need for the PSUs to finalise the wages settlements quickly.

Surplus production of Cement

483. SHRI BAIKUNTHA NATH SAHU: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) the projection of production, supply and demand of cement during the years 1988-89 and 1989-90;

(b) whether there will be surplus production of cement in the country by the end of the Seventh Five Year Plan;

(c) if so. what steps are proposed to be taken to utilise the surplus cement; and

(d) whether Government will export cement if production increased further?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHAL AM): (a) The required information is given below:—

(In million tonnes)

Year	Production (Estimated)	Demand as estimated by Working Group on Cement Industry for Seventh Five Year Plan
1988-89	43.50	46.00
1989-90	49.00	49.00

Year	Production (Estimated)	Demand as estimated by Working Group on Cement Industry for Seventh Five Year Plan
1988-89	43.50	46.00
1989-90	49.00	49.00

(b) and (c). In case of the actual demand falling short of the demand as estimated by the Working Group there may be a marginal surplus of cement by the end of the Seventh Plan Period.

(d) The export of cement has since been decanalised and the cement manufacturers are free to export cement to any country.

Frequent rises in the prices of light Commercial Vehicles

484. SHRI BAIKUNTHA NATO SAHU: SHRI JERLIE E. TARIANG:

Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether there have been frequent rises in the prices of Light Commercial Vehicles;

(b) if so, what are the reasons therefor; and

(c) whether any instructions have been issued to the manufacturers of Light Motor Vehicles to see that the prices are increased in such a way that the market may bear the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SHRI M. ARUNACHALAM): (a) and (b) In the recent past, the light commercial vehical manufacturers, particularly those with Japanese collaboration have had to increase the prices of their vehicles frequently due to the steep appreciation in the value of the yen, its effect on the duties and taxes to be paid by the manufacturers and the rising input costs.

(c) No, Sir.

मारुति कारों का उत्पादन और उनके मूल्यों में वृद्धि

485. **श्री मीर्जा इरशादबेग:** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मारुति उद्योग लिमिटेड ने इस वर्ष तथा पिछले वर्ष कितनी कारों का उत्पादन किया, इन्हें उपभोक्ताओं को किस दाम पर बेचा गया, कारों के किन-किन माडलों पर कीमतों में वृद्धि की गयी और इस वृद्धि के कारण क्या हैं;

(ख) इस समय प्रत्येक राज्य में कितने बिक्री केन्द्र काम कर रहे हैं और क्या उपभोक्ताओं के लाभार्थ इन केन्द्रों में वृद्धि किये जाने की कोई योजना है और जिन राज्यों में ये केन्द्र खोले जाने का विचार है उनके नाम क्या हैं तथा वहां कितने-कितने अतिरिक्त केन्द्र खोले जाने की योजना है;

(ग) मारुति उद्योग लिमिटेड का वार्षिक मुनाफा कितना है; और

(घ) मारुति कारों के पुर्जे कब तक सम्पूर्ण रूप से स्वदेशी हो जायेंगे?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव): (क) 1987-88 तथा 1988-89 (20-2-89 तक) के दौरान मारुति उद्योग लिमिटेड की कारों का उत्पादन तथा उनकी कीमतें विवरण-I में दी गई हैं। मारुति कारों की कीमतों में वृद्धि अमरीकी डालर की तुलना में रुपये का मूल्य गिर जाने तथा कच्चे माल और खरीदे गये हिस्से पुर्जों की लागत में वृद्धि हो जाने के कारण हुई है।

(ख) मारुति, उद्योग लि० के वर्तमान डीलरों के 83 बिक्री केन्द्र हैं और उनका विचार निकट भविष्य में 24 अतिरिक्त बिक्री केन्द्र खोलने का है। विद्यमान तथा